

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री भगवत सिंह देवल

अपील संख्या 61/16

तारीख रजू- 04/05/2016

सीताराम पुत्र गुल्या भीना निवासी कडी झोपडी तहसील गंगपुरसिटी।

बनाम

—अपीलार्थी

सरकार जरिये नायब तहसीलदार, तलावडा।

— रसपो०

निर्णय

दिनांक—16/06/2016

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार, तलावडा द्वारा मिसल संख्या 782/15 में पारित आदेश दिनांक 28/09/2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम कडी झोपडी की आराजी खसरा नम्बर 102 रकवा 0.10 हैक्टर किस्म गै०मु०चरागाह पर संवत् 2072 खरीफ में अनाधिकृत रूप से कब्जा कर काश्त करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थात् दण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने व फसल जब्त कर नीलाम करने के साथ साथ अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलार्थी के अतिचारी होने का कोई रिकार्ड नहीं है ना ही अपीलार्थी को अतिक्रमि आराजी से पूर्व निर्णय पेश की पालना में भौतिक रूप से कब बेदखल किया गया है इसका कोई उल्लेख है। इस प्रकार अदालत कारावास की सजा का जो दण्ड दिया है व निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस में यह भी कच्ची डोल मेड हो रही है जो आज भी मोके पर स्थित है परन्तु पटवारी हल्का ने कार्यालय में बैठकर उक्त अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश की है जिसमें मोके की कोई जांच नहीं की गई है व अदालत मातहत ने भी पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट पर विश्वास करके उक्त अपीलार्थी निर्णय पारित किया है जो खिलाफ कानून होने के कारण निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का वर्णन करते हुए बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस में यह भी तर्क दिया कि अपीलार्थी निर्णय अदालत मातहत द्वारा पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट पर पारित किया गया है जिसमें अपीलार्थी को जिरह का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस में यह भी तर्क दिया कि अदालत मातहत की पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने का कोई रिकार्ड नहीं है ना ही अपीलार्थी को अतिक्रमि आराजी से पूर्व निर्णय की पालना में भौतिक रूप से कब बेदखल किया गया है इसका कोई उल्लेख है। इस प्रकार अदालत मातहत ने अपीलार्थी को बिना दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर पश्चातवर्ती अतिचारी मानकर सिविल कारावास की सजा का जो दण्ड दिया है व निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस में यह भी तर्क दिया कि उक्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र गुलाब माली से क्रय की है व उसी वक्त की कच्ची डोल मेड हो रही है जो आज भी मोके पर स्थित है परन्तु पटवारी हल्का ने कार्यालय में बैठकर उक्त अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश की है जिसमें मोके की कोई जांच नहीं की गई है व अदालत मातहत ने भी पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट पर विश्वास करके उक्त अपीलार्थी निर्णय पारित किया है जो खिलाफ कानून होने के कारण निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेशोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने व अपीलार्थी का अतिचारी भूमि पर पश्चातवर्ती अतिचार पाये जाने के पश्चात ही अपीलार्थी निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की अनियमिता व अवैधानिकता नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

दोनों पक्षों की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि अदालत मातहत ने पटवारी हल्का की अपीलार्थी के विरुद्ध पश्चातवर्ती अतिचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने हेतु धारा 91(3) का नोटिस नियत दिनांक

6/2

अपील पत्रावली संख्या 61/16 सीताराम/सरकार

28/09/15 का जारी किया है जिस पर अपीलार्थी की प्रोपर तामील हुई है व अपीलार्थी अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित हुआ है तथा कब्जा होने से इन्कार किया है तथा भूमि कय किये जाने संबंधी कोई दस्तावेज अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। अतः अपीलार्थी का यह कथन कि उसे सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान नहीं किया गया है मिथ्या है। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचार होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पटवारी हल्का की रिपोर्ट व बयान को एकमात्र आधार मानकर सिविल कारावास की सजा का दण्ड पारित किया है। सिविल कारावास की कठोर सजा का दण्ड पारित करने से पूर्व, पूर्व निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा निर्णय की पालना में बेदखली रिपोर्ट का दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में पत्रावली में शामिल होना आवश्यक है जिससे अपीलार्थी पर पश्चातवर्ती अतिचार की पुष्टि हो सके जिसका इस प्रकरण में अभाव पाया जाता है। अतः बिना दस्तावेजी साक्ष्य के अपीलार्थी के विरुद्ध पारित सिविल कारावास की सजा को न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमें बेदखली, शारित व फसल जब्त कर नीलामी का आदेश तो यथावत रखा जाता है तथा सिविल कारावास की सजा का आदेश निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16/06/2016 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

म. 00115
(भगवत सिंह देवल) 16-6-16
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर